

प्रगतिशील बजट में नियमों की अनदेखी

सुषमा रामचंद्रन

एक ऐसा बजट, जिसका सीधा मकसद उत्तरित के लिए बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना हो, यह मंतव्य अगले साल का बजट बनाने में की गई वार्षिक सरकारी मशक्त की सबसे बढ़िया परिभाषा है। इसमें पिछले बजटों की तुलना में गैर-जरूरी खर्चों की झलक कम है, इनमें सबसे उल्लेखनीय है महामारी की वजह से थमे आर्थिकी के पहिए को पुनः गति देने में पूँजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत का इकाजा करना। इस प्रक्रिया में हालांकि कई ऐसे क्षेत्र छूट गए, जिनको अधिक राजनीतिक संवेदनशीलता और विशेष सहायता की दरकार है। एकमेव दृष्टिकोण रखकर किए गए नए बजटीय प्रस्तावों के पीछे पिछले कुछ महीनों से जोर-शोर से चल रही वह मांग है कि सरकार अर्थव्यवस्था और रोजगार के मौके पुनर्जीवित करने हेतु और ज्यादा आवंटन करे। वर्ष 2022-23 के लिए पूँजीगत व्यय को 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ किया गया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत है। आगामी वर्ष के लिए वित्तीय घाटा 6.9 फीसदी से कम करते हुए 6.4 प्रतिशत रखने का लक्ष्य है। एक दीर्घ-कालीन महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 60 लाख नौकरियां पैदा करने की बात कही गई है। पुनः नौकरियों को लेकर दीर्घकालीन योजना पर ध्यान केंद्रित रखना, ऐसे वर्क पर हो रहा है जब रोजगार संकट को सुलझाने में सरकार की विफलता की आलोचना चहुं ओर पहले से हो रही है। लेकिन निकट काल और उन क्षेत्रों के लिए, जिनमें महामारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके लिए बजट में बहुत कम है। जहां बुनियादी ढाँचा विकास आवंटन राशि में की गई नाटकीय वृद्धि स्वागतयोग्य है वहीं बुरी तरह पस्त पड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की तरफ यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया। होटल व्यवसाय की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए आपातकालीन उधार गारंटी योजना राशि में 50,000 करोड़ की वृद्धि जरूर एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यह उस क्षेत्र के लिए नाकाफी है जो हाल ही में पुनः गति पकड़ने वाली औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। इस बजट की एक अन्य कमजोरी यह है कि अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी मात्रा में निवेश करने से मुद्रा-स्फीटी पर पड़ने वाले दबावों की ओर एकतरफा रवैया अपनाया गया है। दूसरी असफलता है बाहरी अवयवों के प्रभाव को

ध्यान में न रखना, मसलन, बढ़ती तेल कीमतें और उनका प्रभाव खाता-घाटे पर पड़ना। उम्मीद यह थी कि समाज के सबसे निचले पायदान के नागरिक- शहरी हों अथवा ग्रामीण- उन्हें किसी न किसी रूप में सीधी राहत मिलेगी, खासकर कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। जबकि कोई इंकार नहीं कर सकता कि गरीबों में भी अत्यंत दरिद्र वर्ग को फौरी मदद की जरूरत है। मौजूदा सामाजिक भलाई योजनाएं, जैसे कि मुफ्त भोजन और प्रधानमंत्री किसान योजना शलाघा योग्य हैं, किंतु वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को मालूम होना चाहिए था कि इस अनौपचारिक क्षेत्र के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है। रोचक यह कि ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत राशि में वर्ष 2022-23 बजट में कमी की गई है। मनरेगा योजना में आवंटन 98000 करोड़ से घटाकर 73000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। शायद यह कथास लगाकर कि महामारी का प्रकोप घटने से प्रवासी मजदूर पुनः शहरों का रुख करेंगे, जिससे गांवों में रोजगार मांग पर दबाव कम होगा। लेकिन हाल-फिलहाल लग रहा है कि महामारी के दौरान ऐसी योजनाओं के तहत रोजगार की मांग के उछाल में कोई कमी नहीं हो रही है। बजट के सकारात्मक पक्ष में, अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण के लिए अधिक आवंटन होने से इसकी बढ़ोतारी के लिए जरूरी खाद मिलेगी। बड़ी खबर है डिजीटल रुपये का आगाज होना और साथ ही तमाम आभासीय डिजीटल सरमाया की खरीदो-फरोख्त के लिए एक तरह से क्रिप्टो-करेंसी को मान्यता देते हुए इसके जरिए तमाम लेन-देन पर टैक्स लगाना। चूंकि क्रिप्टो करंसी व्यापार की प्रकृति ज्यादातर अनुमान आधारित है, इसलिए 30 फीसदी कर लगाना सही निर्णय है। इसके अलावा आय स्रोत पर 1 फीसदी कर लागू करना यह बताता है कि इस किस्म का लेन-देन अब औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का अंग है, जो कि मौजूदा समय की मांग भी है। क्रिप्टो करंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है क्योंकि कोई नहीं नकार सकता कि अब यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का अंग बन चुकी है। अन्य कुछ नए कदम वास्तविक धरातल पर मददगार होंगे, इनमें भुगतान प्लाटफार्म को बढ़ावा देने को डिजीटल बैंकिंग शुरूआत एक है। देखने में आया है कि डिजीटलीकरण में बढ़ोतारी होना बैंकों के आम कामकाज के भौतिक तौर-तरीकों की समझ न होने से समाज के जिस तबके को दिक्खत होती थी, उनके लिए फायदेमंद है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र

के विनिवेश की बात है, अब लग रहा है कि इसको कुछ धीमा किया गया है, जबकि पिछले बजटों में संसाधन जुटाने को इस उपाय को मुख्य तरजीह दी गई थी। अगले वित्तवर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य 2021-22 के 1.75 लाख करोड़ की बनिस्खत 65000 करोड़ रखा गया है। यह इसलिए भी क्योंकि पिछले विनिवेश लक्ष्यों की प्राप्ति आशातीत न होने से इस मर्तबा अपेक्षा में कमी की गई है। हालांकि पिछले बजट में दो बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करने की पूरी योजना का खाका विस्तार से बताया गया था पर एयर इंडिया बिकना पहला बड़ा परिणाम रहा। यह साफ़ है कि विनिवेश की चाल बहुत मंथर रही है। पिछले बजट में पूंजी जुटाने की रूप रेखाएं काफ़ी तप्सील से बताई गई थीं, इस बार वैसा कोई जिक्र नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि विनिवेश आशा के अनुरूप परिणाम देने में विफल रहा। वेतनभौगोलिक मध्यम वर्ग का नए बजट से मायूस होना स्वाभाविक है क्योंकि हमेशा की तरह आयकर पर छुट मिलने के कायास इस बार भी थे। किंतु राहत के रूप में मिला तो केवल प्रक्रिया में सुधार, जिसके अंतर्गत कर-आकलन करने में त्रुटि की भूल-सुधार अगले दो वित्तीय सालों के अंदर करने की इजाजत दी गई है जबकि परेशानी झेल रहा मध्यम वर्ग भी कुछ राहतों का पात्र है। आगामी चुनाव-पूर्व जनता के अनेक वर्ग मुफ्त की सौगातों की आस लगाए बैठे थे, उन्हें निराशा हुई। इसकी बजाय मोदी सरकार ने वित्तीय स्वास्थ्य के लिहाज से सही बजट पेश किया है, जिसकी नजर मुख्यतः सार्वजनिक निवेश में बढ़ोत्तरी करके महामारी की मार से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को खड़ा कर पुनः पटरी पर लाने पर टिकी है। कई अर्थास्त्रियों ने इस बजट को प्रगतिशील और दूरगामी बताया है जो बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना चाहता है और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार होने से आज बेहतर जरूरी रोजगार मौकों में बढ़ोत्तरी होगा। यह बजट आर्थिक पुनरुत्थान हेतु केवल मध्य और दीर्घकालीन उपायों पर ध्यान दे रहा है जबकि अनेकानेक क्षेत्रों की फौरी जरूरतों को नजरअंदाज़ कर रहा है। बेशक यह औपचारिक क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक है, तभी तो घोषणा के फौरन बाद स्टॉक मार्केट में उछल आया है। परंतु बजट की गुणा-भाग में अनौपचारिक क्षेत्र और समाज के निचले तबके के हितों को इस बार किनारे कर दिया गया है।

लेखिका आर्थिक मामलों की वरिष्ठ पत्रकार हैं

महिला आधिकारों के संघर्ष को नयी ताकत

रमेश ठाकुर

पाक सुप्रीम कोर्ट में पहली मर्तवा कोई महिला जज नियुक्त हुई है। उनकी नियुक्ति किसी की दया या सिफारिश पर नहीं, अपनी मेहनत और काविलियत के बूते उन्होंने यह मुकाम पाया है। बुर्क-पर्दे में अपना समृद्धा जीवन जीने वाली पाकिस्तानी महिलाओं को जस्टिस आयशा मलिक की ताजपोशी ने उम्मीदों का नया संबल दिया है, जिसकी राह वहां की आधी आबादी आजादी से ताक रही थीं। ऐसी उम्मीद की खुशी पहली बार उनके हिस्से आई है। महिलाओं को मुकम्मल हक्-हकूम दिलवाने में जस्टिस आयशा मलिक की पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज के रूप में नियुक्ति किसी सपने जैसी है। पूरा जगत वाकिफ है कि वहां की महिलाओं के अधिकारों को कैसे सरेआम रौदा जाता है। घर से बाहर निकलने की भी मनाही रही है, जो कार्य पुरुष करते हाँ, उसे कोई महिला करे, ये वहां के मुला-मौलियों को कभी नहीं भाया। किसी महिला ने हिम्मत दिखाई भी तो उसके खिलाफ फतवा या रुढ़िवादी कठोर बदिशें लगा दी जाती रही हैं। लेकिन आयशा शायद उस पुरानी प्रथा को बदल पाएंगी। उनकी नियुक्ति महिलाओं को संबल देंगी। पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय इस्लामी गणराज्य की सर्वोच्च अदालत जरुर रही है, पर न्यायिक व्यवस्था में हमेशा से भेदभाव हुआ। शरियत कानून को मान्यता ज्यादा दी गई, जो सदैव पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिन्दु रहा है। वहां की आधी आबादी से संबंध रखने वाली बदहाली की दर्दनाक तस्वीरें जब दिमाग में उमड़ती हैं तो लगता है कि कट्टर इस्लामिक मुल्क में एक महिला का सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाना अपने आप में करिश्मा है। जज बनने से पहले भी आयशा मलिक अपने काम

को लेकर चर्चा में रहीं। अपने स्वाभिमान से उन्होंने वसमझीता नहीं किया। उनका नाम आज से दस-पंद्रह रुप हले तब सामने आया था जब उन्होंने भारतीय कैदी सरबक सिंह के पक्ष में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने केस न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़े, राजनीति नहीं है चाहिए। उनके बयान पर तब पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ विरोधियों ने उन्हें भारत जाने तक को कह दिया था। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। हालांकि छुटपुट विरोध अब भी हो रहा है। फिलहाल उनके नाम की मंजूरी हो चुकी है। पद ग्रहण कर लिया है। महिलाओं से जुड़े केसों को वह मुख्य रूप से देखा करेंगी। उनकी ताजपाशी से अब वहाँ की निचली अदालतों और हाईकोर्ट में भी महिला जजों की संख्या में इजाफा होगा। भारत के लिहाज से भी आयशा की नियुक्ति अहम है। शायद इसके बाद उनकी सोच में कछ बदलाव आए। पाकिस्तान



तीन जून, 1966 को जन्मी थीं। आम लोगों की तरह गांव के ही सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद कराची के गवर्नमेंट कॉलेज ॲफ कॉर्मस एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक किया। लॉ की पढ़ाई उन्होंने लाहौर के कॉलेज ॲफ लॉ से की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में मेरसाच्यूसेट्स के हॉवर्ड स्कूल ॲफ लॉ से भी शिक्षा प्राप्त की। खुद छोटे बच्चों को ट्यूशन देती थीं, जिससे अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला करती थीं। पढ़ने में अच्छी थीं, तभी उन्हें स्कॉलरशिप मिली। आयशा को 1998-1999 में 'लंदन एच गैमोन फेलो' के लिए भी चुना गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अमेरिका में भी अपना करिअर शुरू कर सकती थीं, लेकिन उनको अपने यहां महिलाओं की बदहाली को दूर करना था। कुछ अलग करने का जज्बा लेकर ही वह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। आयशा अमेरिका से 2003 में अपने मुल्क लौट आयी थीं। वहां से आने के बाद आयशा मलिक ने कराची की निचली अदालत में वकालत शुरू की।

फखरुद्दीन इब्राहिम एंड कंपनी से जुड़ी। बाते एक दशक से उन्होंने खूब नाम कमाया और कई मशहूर कानूनी फर्मों के साथ जुड़कर कई नामी केसों को सुलझावाया। निश्चित रूप से आयशा की नियुक्ति पाकिस्तान में नया इतिहास लिखेगी। वहां महिलाओं के हालात कैसे हैं, दुनिया में किसी से छिपे नहीं हैं। उम्मीद ऐसी भी की जानी चाहिए कि आयशा के जरिए दुनिया का नजरिया पाकिस्तान के प्रति बदले।

आज के कार्टून



ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਸ

श्रीराम शर्मा आचार्य/ चोट खाया हुआ सांप आक्रमणकारी पर ऐसी फूफकार मारकर दौड़ता है कि उसके होश छूट जाते हैं। सांसारिक व्यथाओं से विश्वस्त मनुष्य की भी ऐसी ही स्थिति होती है। जब मनुष्य को पीड़ाएं चारों ओर से घेर लेती हैं, कोई सहारा नहीं सूझता तो वह निष्ठापूर्वक अपने परमेश्वर को पुकारता है। हार खाए हुए मनुष्य की कातर पुकार से परमात्मा का आसन हिल जाता है। उन्हें सारी व्यवस्था छोड़कर भक्त की सेवा के लिए भगवना पड़ता है। ऐसा समय आता है जब मनुष्य ससार को भूलकर कुछ क्षण के लिए ऐसे दिव्य लोक में पहुंचता है, जहाँ उसे असीम सहानुभूति और शात शाति मिलती है। अंतकरण की समस्त वासनाएं विलीन हो जाती हैं, इदियों की चेष्टाएं शांत हो जाती हैं। हिरण्यकश्यप की हठधर्मिता से दुखी बालक प्रह्लाद ने उसे बार-बार पुकारा, उसका नारायण बार-बार उसकी मदद के लिए दौड़ा। मनुष्य बुलाए और वह न आए ऐसा कभी हुआ नहीं। द्रौपदी जान गई थी कि सभा में उसे बचाने वाला कोई नहीं है। दुश्शासन चीर खींचता है। लाज न चली जाए, इस भय से निर्बल नारी दीनानाथ को पुकारती है। भगवन श्रीकृष्ण आते हैं और उसका चीर को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। देवासुर संग्राम की कथाओं में ऐसे अनेक वर्णन हैं। बहुत से लोग हैं, जो ईश्वर और उसके अस्तित्व को मानने वे इनकार करते हैं, पर यदि भली भांति देखा जाए तो मूढ़ताग्रस्त व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आश्वर्य हमारे सामने बिखरा पड़ा है। उसे देखकर भी जिसका विवेक जाग्रत न हो, कौतूहल पैदा न हो, उसे और कहा भी क्या जाएगा? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यह दृश्य आप किसी अन्य ग्रह में बैठे देख रहे होते, तो समझते मनुष्य का अभिमान कितना छोटा है। विशाल ब्रह्माण्ड की तुलना में वह चीटी से भी हजार गुना छोटा लगेगा। अनंत आकाश और उस पर निरंतर होती रहती ग्रह-नक्षत्रों की हलचल, सूर्य, चन्द्रमा, सागर, पर्वत, नदियां, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य आदि के स्वयं के बदलते हुए क्षण क्या यह सब मनुष्य का विवेक जाग्रत करने के लिए काफी नहीं है? परमात्मा का अस्तित्व मानने के लिए क्या इतने से संतोष नहीं होता? विचारणा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सोचेगा। आदिकाल से लेकर अब तक जितने भी संत, महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने भी आत्म कल्याण या लोक कल्याण की दिशा में कदम उठाया है, उन सबने परमात्मा-ईश्वर का आश्र्य मुख्य रूप से लिया है।

સ્થ-દોકુ નવતાલ -2039								
9			5	3		8		
2						9	6	
	7		6		1		2	
3		8						
4	5	7		8		3	1	2
						7		9
	8		2		5		3	
	2	4						8
		3		6	9			4

3	5	9	6	1	2	8	7	4
2	6	8	9	7	4	1	3	5
7	4	1	3	8	5	2	6	9
1	2	6	5	3	8	9	4	7
8	9	3	4	2	7	5	1	6
5	7	4	1	6	9	3	8	2
4	3	2	8	5	6	7	9	1
9	8	7	2	4	1	6	5	3

3	5	9	6	1	2	8	7	4
2	6	8	9	7	4	1	3	5
7	4	1	3	8	5	2	6	9
1	2	6	5	3	8	9	4	7
8	9	3	4	2	7	5	1	6
5	7	4	1	6	9	3	8	2
4	3	2	8	5	6	7	9	1
9	8	7	2	4	1	6	5	3
6	1	5	7	9	3	4	2	8

स-टोक नवताल -2039

आप से नीचे

- | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|
| य | हूं | दी | अ | बु | रो | ध | क्षे |
| ह | वा | स्त | व | हि | ओँ | धी | |
| दे | व | र | | ता | क | त | व |
| श | र्त | | पा | र | स | स | ल मा |
| मा | | | पी | | क | स | म ला |
| जा | न | म | अ | | गा | य | व |
| वे | | शा | र | दा | इं | ना | च |
| म | ठ | ल | | ल | की | जो | र |
| न | | | अं | त | जं | स | त्या |
| | वा | हि | श | बु | र्ग | बू | ग |

भ्रष्टाचार प्रतियोगिता में

&

भ्रष्टाचार की जानकारी देने

**National Rights Group
Youtube Channel**

krantisamay@gmail.com



9879141480

fight against corruption india

**भारत में भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ाई**